

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-2/2012./सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 18/01/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- टी. चौइथराम हास्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा विकिरण परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत टी चौइथराम हास्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच / उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

संक्र.	समिति द्वारा अनुशंसित उपचार / जांच	समिति द्वारा अनुशंसित दरें
	Radiation Therapy on primus Linear Accelerator unit from siemens	
1.	IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)	रु. 95,000 / -
2.	3 D Conformal Therapy	रु. 60,000 / -
3.	2 D Complex Conventional Radiotherapy	रु. 45,000 / -
4.	2 D Simple Conventional Radiotherapy	रु. 40,000 / -
5.	Conventional Radiotherapy-A	रु. 35,000 / -
6.	palliative radictotherapy single	रु. 20,000 / - (RS. 2,000/- Single Fraction maxiem 10 Fraction)
7.	Electron Therapy per Fraction	रु. 600 / -
	Brachytherapy	
1.	Intracavitary (ICRT) Single Fraction	रु. 5,000 / -
2.	Surface Application, Single Fraction	रु. 4,000 / -
3.	Intra Luminal Brachytherapy (ILRT) Single Fraction	रु. 6,000 / -
4.	Bronchus (ILRT)	रु. 6,000 / -
5.	Radical prostate	रु. 12,000 / -
6.	Intracavitary (ICRT)	रु. 10,000 / -
7.	Interstitial	रु. 10,000 / -



2/- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से मंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के दिक् पावता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसल्टेंट को दिखाना होगा। कंसल्टेंट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच स्थित करने वह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (सेल विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति रकत निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे पहली चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जित निर्धारित दरों (एम्बुड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्हीं दरों पर सेवाएँ ही प्रदान की जानेगी।
- 10-संस्थान को प्रतिवर्ष उक्त रकत व अन्तर्गत संवीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

3/- यह स्वीकृति बिना जिला के उपाय्य क्रमांक 41/12/2106/11/नि/चार, दिनांक 01/01/2012 द्वारा दी गई अध्यादेश के तहत जारी की गई है।

मुख्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

01/01/2012

(डी.डी.चक्रनारायण)

अवर सचिव

मुख्य प्रदेश शासन

लोक रक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-2/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 18/01/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 41/12/2106/11 नियम/चार, दिनांक 24/01/2011 के संदर्भ में अग्रेषित ।

3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल ।

5- संयुक्त संचालक, (एमआर) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।

6- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र. ।

7- संगोष्ठी संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर, म.प्र. ।

8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर

9- सेवा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।

10- संचालक, टी. बी. इन्फेक्शन हॉस्पिटल इन्दौर ।

डी.बी. 205/11/401

अवर सचिव

म.प्र. प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग